समक्ष एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति

यश पाल सिंह और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

एम/एस प्रेम चंद विजय कुमार, प्रतिवादी

सीआरएल एम नंबर 2002 की 10748/M

1 दिसम्बर, 2003

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881- धारा 138 और 142 - चेक का अनादर- धारा 138 के तहत चेक नोटिस का अनादर- आरोपी द्वारा भुगतान शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज न करने के आश्वासन पर - दूसरी बार चेक की प्रस्तुति - फिर से चेक का अनादर- चेक के दूसरी बार अनादर के बाद सीमा की अवधि के भीतर दर्ज शिकायत - क्या समय की सीमा के भीतर दर्ज की गई शिकायत - क्या समय प्रतिबंधित है। हां- चेक बाउंस होने पर कार्रवाई का कारण केवल एक बार उठता है - चेक के बाद अनादर से कार्रवाई का कोई नया कारण पैदा नहीं होगा - शिकायत के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करते हुए याचिका की अनुमति दी जाती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 138 के तहत 17 फरवरी, 1995 को नोटिस जारी करने के बाद शिकायतकर्ता के समक्ष कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है। नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ था और शिकायत 3 अप्रैल,1995 तक दायर की जा सकती थी, जिसे वे दायर करने में विफल रहे। ड्रॉअर द्वारा चेक को फिर से प्रस्तुत करने के वादे और बाद में इसके अनादर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे कार्रवाई का नया कारण नहीं बनेगा। धारा 14'2 (बी) के प्रावधान हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि यदि अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने के एक महीने के भीतर शिकायत नहीं की जाती है तो कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी। इसलिए, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पीएस हुंडल।

प्रतिवादियों के वकील शैलेंद्र जैन।

निर्णय

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर इस याचिका में 28 अगस्त, 1995 की शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (संक्षिप्तता के लिए) की धारा 138 के उल्लंघन की शिकायत की गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, करनाल द्वारा पारित दिनांक 29 जनवरी, 2002 के आदेश को रद्द करने के लिए एक और अनुरोध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के आरोप मुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने परिसीमा की याचिका (आदेश अनुलग्नक पी-8) स्थापित की है।

2. तत्काल याचिका के निपटान के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अधिनियम की धारा 138 के तहत 28 अगस्त, 1995 को एक शिकायत दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी मेसर्स प्रेम चंद विजय कुमार, कमीशन एजेंट और राइस डीलर, तरावड़ी धान और चावल का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने आरोपी फर्म को धान भेजा था, जिसमें आरोपी - याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 भागीदार हैं। धान का कुल मूल्य 49,21,482,72 रुपये होने का दावा है। यह भी कहा गया है कि आरोपी-याचिकाकर्ताओं ने 44,06,429 रुपये और शेष राशि का भुगतान किया था। अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 5,15,053.72 बकाया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि चेक सं 2007-12 के माध्यम से 5,15,053.72 रुपये की राशि का चेक जारी किया गया। 27 जनवरी, 1995 की एलआर 882128 आरोपी द्वारा जारी की गई थी - याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के पक्ष में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लाडवा शाखा में लिए गए प्रतिवादी - खाता संख्या 954 के माध्यम से। चेक पर आरोपी याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे और आरोपी-याचिकाकर्ता नंबर 2 सत गुरु राइस ट्रेडर्स, नई दिल्ली नामक फर्म का भागीदार है। उपर्युक्त चेक 3 फरवरी, 1995 को अनादरित किया गया था और इसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तरावड़ी

द्वारा 6 फरवरी, 1995 को अपर्याप्त निधियों के साथ लौटा दिया गया था। शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने 17 फरवरी, 1995 को यूपीसी के साथ अधिनियम की धारा 138 के तहत एक नोटिस भेजा और अभियुक्तों से अनुरोध किया कि वे 15 दिनों की अवधि के भीतर ब्याज @ 24% प्रति वर्ष के साथ भुगतान करें। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी-याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 द्वारा दिए गए आश्वासन पर कि वे भुगतान करेंगे, शिकायतकर्ता प्रतिवादी ने शिकायत दर्ज नहीं की। यह दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी से एक वादा किया गया था कि भुगतान जून, 1995 में किया जाएगा। हालांकि, जब भुगतान नहीं किया गया, तो शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने फिर से आरोपी-याचिकाकर्ताओं से संपर्क किया। इस बार, उन्होंने आश्वासन दिया कि चेक फिर से प्रस्तुत किया जाएगा और फिर इसे भुनाया जाएगा। तदनुसार, अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आश्वासन पर, चेक 6 जुलाई, 1995 को फिर से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे 10 जुलाई, 1995 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तरावरी द्वारा इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया था कि यह व्यवस्था से अधिक है, जिसका दूसरे शब्दों में अर्थ अपर्याप्त धन है। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 138 के तहत अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस दिया और आरोपी-याचिकाकर्ताओं को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने के लिए कहा। अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के माध्यम से एक जवाब भेजा, जो 16 अगस्त, 1995 को शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के वकील द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि नोटिस प्राप्त होने से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी।

3. आरोपी-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक आवेदन में, उन्हें आरोपमुक्त करने के लिए प्रार्थना की गई थी। आवेदन में कहा गया है कि 17 फरवरी ,, 1995 को पहला नोटिस जारी होने के बाद, परिसीमा अवधि 3 अप्रैल, 1995 तक उपलब्ध थी और 28 अगस्त, 1995 को शिकायत दर्ज किए जाने के बाद, इसे समय द्वारा रोक दिया गया था। आरोपमुक्त करने के लिए दायर आवेदन के जवाब में, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने कहा कि आरोपी-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं और यह सबूत का विषय है कि क्या शिकायत समय सीमा के भीतर थी या समय सीमा के भीतर थी। यह भी कहा गया कि आरोपी-याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि वे संबंधित राशि जमा करेंगे और यदि चेक फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे भुनाया जाएगा। इसलिए, परिसीमा अवधि को चेक के अनादरण की

तारीख से गिना जाना आवश्यक है, जब इसे दूसरी बार प्रस्तुत किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आरोपी याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपमुक्त करने के लिए दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि -

> "जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में चेक विवाद फिर से प्रस्तुत किया गया और 10 जुलाई, 1995 को वापस कर दिया गया और शिकायतकर्ता ने 24 जुलाई, 1995 को पंद्रह दिनों के भीतर आरोपी को एक नोटिस जारी किया, जिसका 24 जुलाई, 1995 को आरोपी द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर जवाब दिया गया, जिसका जवाब आरोपी ने 10 अगस्त को दिया। 1995 में शिकायतकर्ता के वकील द्वारा प्राप्त शिकायत 16 अगस्त, 1995 को प्राप्त की गई और वर्तमान शिकायत 28 अगस्त, 1995 को दायर की गई थी। इसका मतलब है
>
> उन्होंने कहा कि वर्तमान शिकायत 10 अगस्त, 1995 को आरोपियों द्वारा अपने वकील के माध्यम से दायर जवाब के एक महीने के भीतर दायर की गई है। इसके अलावा, आरोपी के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं और यह आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करने का चरण नहीं है। "

4. आरोपी याचिकाकर्ताओं के वकील श्री पी. एस. हुंडल ने तर्क दिया है कि चेक के अनादरण पर शिकायत दर्ज करने का कारण केवल एक बार उठता है और चेक की किसी भी प्रस्तुति और इसके अनादरण पर कार्रवाई का कोई नया कारण उत्पन्न नहीं होगा। वकील ने आगे तर्क दिया है कि एक बार चेक के पहले अनादरण पर नोटिस जारी किया गया है और नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो आदाता को कार्रवाई के उस कारण का लाभ उठाना होगा और शिकायत दर्ज करनी होगी। . उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने सदानंदन भद्रन बनाम माधवन सुनील कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया है, (1). विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया स्पष्ट दृष्टिकोण यह है कि कार्रवाई का कारण केवल एक बार उत्पन्न होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 142 द्वारा अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (बी) के साथ पढ़ा गया है। विद्वान वकील के अनुसार, एक बार ड्रॉअर द्वारा अधिनियम की धारा 138 के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो एक महीने की अवधि के भीतर, आदाता दराज के खिलाफ अभियोजन शुरू

कर सकता है और तदनुसार वर्तमान मामले में शिकायत 3 अप्रैल, 1995 तक दायर की जा सकती थी, जो कि धारा 138 के तहत नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर थी। शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा जारी अधिनियम। चेक की बाद की प्रस्तुति से कार्रवाई का कोई नया कारण पैदा नहीं होगा और इसलिए, शिकायत के साथ-साथ बाद की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

5. शिकायतकर्ता प्रतिवादी के वकील श्री शैलेंद्र जैन ने तर्क दिया है कि सबसे पहले 29 जनवरी, 2002 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ, केवल एक पुनरीक्षण याचिका सक्षम है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है। मामले के गुण-दोष के आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चेक की बाद में प्रस्तुति का तर्क आरोपी-याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए बयान में शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दिखाया गया ईमानदार विश्वास था कि चेक हो सकता है। इसे फिर से प्रस्तुत किया जाएगा और इसे भुनाया जाएगा। अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उपर्युक्त बयान के आधार पर विद्वान वकील के अनुसार, चेक बाद में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 6 जुलाई, 1995 को फिर से अनादरित किया गया था और चेक के अनादर के संबंध में 10 जुलाई, 1995 को पत्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद, 24 जुलाई, 1995 को नोटिस जारी किया गया और नोटिस के 15 दिनों के भीतर कोई भुगतान नहीं किया गया और 15 दिनों की समाप्ति पर, 30 दिनों की सीमा की अवधि को गिना जाना है और शिकायत 28 अगस्त, 1995 को दायर की गई थी, जो सीमा की अवधि के भीतर है। अपनी दलील के समर्थन में विद्वान वकील ने एक फैसले पर भरोसा जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम मैसर्स गैलेक्सी ट्रेडर्स एंड एजेंसीज लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया है।

6. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि आरोपी-याचिकाकर्ताओं का मामला सदानंदन के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जहां इसी तरह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है क्योंकि वहां भी एक आरोपी द्वारा किए गए अनुरोध पर, चेक को फिर से प्रस्तुत किया गया और चेक के दूसरी बार अनादरण के बाद सीमा की अवधि के भीतर दायर शिकायत को समय सीमा के भीतर दायर किया गया। अधिनियम की धारा 138 और धारा 142 पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:—

138. 'जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए लिया गया कोई चेक, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए, बैंक द्वारा अवैतनिक लौटा दिया जाता है, या तो उस खाते के क्रेडिट में खड़ी राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक, ऐसे व्यक्ति को अपराध माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना तक हो सकता है, या दोनों के साथ।

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि-

1. चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस तारीख को इसे तैयार किया गया था या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी आसान हो।

2. आदाता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक की वापसी के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, चेक के दराज को लिखित में एक नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है: और

3. इस तरह के चेक का आहरणकर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के नियत समय में आदाता को या जैसा भी मामला हो, उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

142. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी -

7.कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय आदाता द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के बिना या, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में।

1. ऐसी शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है जिस दिन धारा के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है138:

2. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कमतर की कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

8.धारा 138 के प्रावधान की व्याख्या सदानंदन के मामले (सुप्रा) में उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई है, जो निम्नानुसार है।—

"उपरोक्त धारा के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, यह देखा गया है कि इसका मुख्य भाग एक अपराध बनाता है जब बैंक द्वारा चेक को उसमें उल्लिखित किसी भी कारण से भुगतान नहीं किया जाता है .। हालांकि, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परंतुक में तीन शर्तें दी गई हैं।

उपर्युक्त धारा की प्रयोज्यता के लिए और उस मामले के लिए, ऐसे अपराध का निर्माण और शर्तें हैं:

(i) चेक जारी होने के छह महीने के भीतर या इसकी वैधता के पूर्वावलोकन, जो भी पहले हो, के भीतर बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, (ii) आदाता को चेक के अवैतनिक वापस आने के बाद पंजीकृत नोटिस द्वारा भुगतान की मांग करनी चाहिए: और (iii) यह कि आहरणकर्ता नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल होना चाहिए। यह केवल तभी होता है जब उपरोक्त सभी तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं कि धारा 138 के तहत अपराध के लिए अभियोजन शुरू किया जा सकता है। जहां तक पहली शर्त का संबंध है, धारा 138 के परंतुक के खंड (क) में आदाता पर उसकी वैधता की अवधि के दौरान अनादरित चेक को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके अलावा; व्यावसायिक लेनदेन के दौरान यह असामान्य नहीं है कि अपर्याप्त धन या इसी तरह के कारणों के कारण चेक वापस कर दिया जाता है और कुछ समय बाद आदाता द्वारा फिर से प्रस्तुत किया जाता है। अपनी इच्छा से या दराज के अनुरोध

पर, इस उम्मीद में कि इसे भुनाया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, आदाता का प्राथमिक हित अपना पैसा प्राप्त करना है, न कि दराज का अभियोजन, जिसका सहारा, आम तौर पर, मजबूरी से लिया जाता है और विकल्प नहीं होता है। उपरोक्त कारणों के लिए यह माना जाना चाहिए कि चेक को इसकी वैधता की अवधि के दौरान कितनी भी बार प्रस्तुत किया जा सकता है। वास्तव में कुमारसेन (1991) केर एलटी 893 में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ को छोड़कर सभी उच्च न्यायालयों का यही सुसंगत दृष्टिकोण है, जिसने इस टिप्पणी के साथ असहमति व्यक्त की कि चेक के पहले अनादर के लिए, केवल अभियोजन शुरू किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन के लिए कार्रवाई के एक से अधिक कारण नहीं हो सकते हैं।

. 9. यह उल्लेख करना भी उचित है कि धारा 142 यह स्पष्ट करती है कि सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की लिखित शिकायत का संज्ञान ले सकता है यदि शिकायत अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है। इसके बाद सदानंदन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया।

मामला (सुप्रा) कि कार्रवाई के कारण का अर्थ हर उस तथ्य से होगा जिसे किसी अधिकार का समर्थन करने या निर्णय प्राप्त करने के लिए स्थापित करना आवश्यक है और तदनुसार एक शिकायतकर्ता को अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दराज पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने के लिए साबित करना आवश्यक है और वे तथ्य निम्नानुसार हैं:—

1. यह चेक ऋण/देयता के निर्वहन के लिए राशि के भुगतान के लिए तैयार किया गया था और चेक बाउंस हो गया था.

2. कि चेक निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था •

3. कि आदाता ने निर्धारित अवधि के भीतर दराज को लिखित में नोटिस देकर पैसे के भुगतान की मांग की; और

4. नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर ड्रॉअर भुगतान करने में विफल रहा।

10. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम की धारा 142 के खंड (बी) के संदर्भ में, कार्रवाई के कारण शब्द का सामान्य अर्थ नहीं लिया जा सकता है और इसे प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए क्योंकि धारा 142 का खंड (बी) केवल एक तथ्य को संदर्भित करता है। इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के विचार निम्नानुसार हैं: ...

> "यदि हम कार्रवाई के कारण शब्द के सामान्य, अर्थ के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उपरोक्त तथ्यों में से प्रत्येक कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा होगा, लेकिन फिर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 142 का खंड (बी) इसे एक प्रतिबंधात्मक अर्थ देता है, इसमें, यह केवल एक तथ्य को संदर्भित करता है जो कार्रवाई के कारण को जन्म देगा और वह है बनाने में विफलता। . नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान। इस तरह के प्रतिबंधात्मक अर्थ देने के पीछे का कारण खोजना दूर नहीं है। धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत परिकल्पित 15 दिनों की अवधि के भीतर पैसे का भुगतान करने में ड्रॉअर की विफलता के परिणामस्वरूप, ड्रॉअर का दायित्व उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए और धारा 142 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए एक महीने की अवधि उत्पन्न होती है।

तदनुसार गणना की जानी चाहिए। अधिनियम की उपरोक्त दो धाराओं को संयुक्त रूप से पढ़ने से संदेह के लिए कोई जगह नहीं बचती है कि धारा 142 (सी) के अर्थ के भीतर कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है और केवल एक बार उत्पन्न हो सकता है।

11.फैसले के पैरा 7 और 8 में अकेले कार्रवाई के पहले कारण के उत्पन्न होने पर दराज के अभियोजन के लिए और भी कारण दिए गए हैं, जो निम्नानुसार है:__

"धारा 138 और 142 की भाषा के अलावा, जो स्पष्ट रूप से कार्रवाई के केवल एक कारण को दर्शाती है, अन्य दुर्जेय बाधाएं हैं जो कार्रवाई के क्रमिक कारणों की अवधारणा को नकारती हैं। उनमें से एक यह है कि एक चेक के अनादर के लिए, केवल एक अपराध हो सकता है और ऐसा अपराध धारा 138 के परंतुक के खंड (बी) के अनुसार दिए गए नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर दराज द्वारा तुरंत किया जाता है। इसका मतलब यह है कि बाद में अनादरण पर नए नोटिस की सेवा के बाद इसी तरह की विफलता के लिए, दराज किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है और न ही पहले अपराध को गैर-कानूनी माना जा सकता है ताकि आदाता को दूसरे अपराध को पहला मानते हुए शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया जा सके। उस स्तर पर, यह आदाता पर मुकदमा चलाने के अधिकार की छूट का सवाल नहीं होगा, बल्कि एक अपराध के लिए दराज के समाधान का सवाल होगा, जो पहले से ही उसके द्वारा किया गया है और जिसे उसके द्वारा फिर से नहीं किया जा सकता है।

12. कार्रवाई के क्रमिक कारणों की अवधारणा की स्वीकृति के लिए एक अन्य बाधा यह है कि यह धारा 142 के खंड (सी) के तहत सीमा की अवधि को अनिवार्य बना देगा, क्योंकि, एक आदाता जो एक महीने के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करने में विफल रहता है और इस तरह दराज पर मुकदमा चलाने के अपने अधिकार को खो देता है, चेक की नई प्रस्तुति और उसके अनादरण के आधार पर शिकायत दर्ज करके उपरोक्त सीमित खंड को दरकिनार कर सकता है। चूंकि विधियों की व्याख्या में, न्यायालय हमेशा यह मानता है कि विधायिका ने उसके प्रत्येक भाग को एक उद्देश्य के लिए सम्मिलित किया है और विधायी इरादा यह है कि प्रत्येक

इसका प्रभाव होना चाहिए, उपरोक्त निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जो शिकायत को अनिवार्य बनाने की अवधि को सीमित करने का प्रावधान करेगा।

13. जब सदानंदन के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्रवाई का एक पूरा कारण था। जो अधिनियम की धारा 138 के तहत 17 फरवरी, 1995 को नोटिस जारी करने के बाद शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को उत्पन्न हुआ है। नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ था और शिकायत 3 अप्रैल, 1995 तक दायर की जा सकती थी, जिसे वे दायर करने में विफल रहे। ड्रॉअर द्वारा चेक को फिर से प्रस्तुत करने के वादे और बाद में इसके अनादर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे कार्रवाई का नया कारण नहीं बनेगा। धारा 142 (बी) के प्रावधान हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि यदि अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने के एक महीने के भीतर शिकायत नहीं की जाती है तो कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी। इसलिए, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

14. जहां तक डालमिया सीमेंट के मामले (सुप्रा) के मामले में फैसले का संबंध है, जैसा कि शिकायतकर्ता प्रतिवादी के वकील द्वारा भरोसा किया गया है, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सदानंदन के मामले (सुप्रा) को इस आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था कि आदाता द्वारा भेजे गए नोटिस को आदाता द्वारा आदाता को एक सूचना भेजकर विवादित किया गया था कि उसे एक खाली लिफाफा मिला था और, इसलिए, आदाता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए भुगतानकर्ता के पास कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। इस पहलू पर जोर देते हुए, डालमिया सीमेंट के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार टिप्पणी की है: —

> 7. सदानंदन भद्रन बनाम माधवन सुनील कुमार मामले में, (1998) 6 एससीसी 514: (1998 एआईआर एससीडब्ल्यू 2902: एआईआर 1998 एससी 3043: 1998 क्रि। एलजे 4066, इस न्यायालय ने माना कि धारा 138 के परंतुक के खंड (ए) ने ऐसा किया। आदाता पर इसकी वैधता की अवधि के दौरान अनादरित चेक को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। चेक की प्रत्येक प्रस्तुति और उसके अनादरण पर एक नया अधिकार प्राप्त होता है और

कार्रवाई का कारण नहीं होता है। अत: चेक का प्राप्तकर्ता या धारक, अधिनियम की धारा 138 के खंड (ख) के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पूर्व-निर्धारित कार्रवाई किए बिना चेक प्रस्तुत कर सकता है ताकि वह ऐसे अधिकार का प्रयोग कर सके।

चेक की वैधता के दौरान किसी भी समय। लेकिन एक बार चेक के ड्रॉअर को अधिनियम की धारा 138 के खंड (बी) के तहत एक नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद, आदाता या चेक धारक चेक को फिर से प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को खो देता है क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में विफलता होने पर कार्रवाई का कारण प्राप्त होता है और सीमा की अवधि चलने लगती है जिसे किसी भी खाते से रोका नहीं जा सकता है। इस अदालत ने जोर देकर कहा कि "यह कहने की जरूरत नहीं है कि शिकायत दर्ज करने से एक महीने की अवधि को उस तारीख से तुरंत बाद माना जाएगा जिस दिन दराज द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है। (जोर दिया गया)

15. उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सदानंदन भद्रन बनाम माधवन सुनील कुमार और डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम गैलेक्सी ट्रेडर्स एंड एजेंसीज लिमिटेड (सुप्रा,) के मामले के बीच एक स्पष्ट अंतर स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाया गया सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि यह केवल कार्रवाई का पहला कारण है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 138 परंतुक (बी) के तहत नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि की समाप्ति पर एक दराज को अभियोजन शुरू करने के लिए सशस्त्र किया जाएगा। यूनिप्लास इंडिया लिमिटेड बनाम राज्य (3) के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन (4) और एसआईएल आयात, यूएसए बनाम एक्जिम सहायक रेशम निर्यातक (5) के मामलों में अदालत। इसलिए, मेसर्स डालमिया सेमेनुस मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के शिकायतकर्ता-प्रतिवादी को कोई लाभ नहीं दिया जा सका।

16. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह याचिका सफल होती है। शिकायत के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 29 जनवरी, 2002 के आक्षेपित आदेश। प्रथम श्रेणी, करनाल और उसके बाद की किसी भी अन्य कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी , हरियाणा